जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 296 प्रभात जालोर, शनिवार 1 फरवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

केन्द्र सरकार ने उद्देश्य पर फोकस कर प्रगति की- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के बजट सत्र में दिये अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर प्रसन्नता जताई

- उन्होंने कहा कि देश निर्णयों को लागू होते देख रहा है। इसमें गरीब महिलाओं व युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
- युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इन्टर्नशिप मिलेगी, जिससे उनके लिये रोजगार के अवसर खुलेंगे।

नई दिल्ली, 31 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में उद्देश्य की एकता पर बल दिया। उन्होंने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" वक्फ अधिनियम, पूर्वोत्तर में शांति तथा मध्यम वर्ग, महिलाओं, एस सी, एस टी एवं ओ बी सी समुदायों पर फोकस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति के लिये सरकार की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। संविधान 75 साल पूरे कर चुका है। मैं बाबा अंबेडकर समेत अन्य संविधान निर्माताओं को नमन करती हूं। राष्ट्रपति ने महाकुंभ का जिक्र किया और वहां भगदड़ में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश निर्णयों को लागू होते देखरहा है। इसमें गरीब, महिलाओं, युवाओं आदि को प्राथमिकता दी जा रही है। 3 करोड़ परिवारों को घर देने का फैसला हुआ है। सरकार ने गांव में आबादी के लिए सौमित्र योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा सौमित्र कार्ड जारी किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 41 हजार करोड़ की राशि वितरित की गई है। जनजातीय लोगों के लिए भी 80 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ ावा दिया जा रहा है और हमारा पशुधन मजबूत हो रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी, जिससे उनके लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत25 हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए 70 हजार करोड़ का प्रावधान हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 6 माह में 17 नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। 10 साल में विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़े हैं। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बड़ा कदम है। स्वयंसहायता समूह के तहत महिलाओं को मजबूत किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के द्वारा निर्मित गगनयान से एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। भारत ने अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग आसान कर दिया है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। शतरंज चैपियनशिप में भी भारत का परचम लहराया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है। कोविड के युद्ध जैसे हालात के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थायित्व दिखाया है, वह उसकी शक्ति का उदाहरण है। आज भारत तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख ग्लोबल प्लेयर है। यूपीआई से विकसित देश भी प्रभावित हैं। 50 फीसदी से ज्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहा है। इसकी सुविधा बड़े लोगों से लेकर छोटे दुकानदार तक ले रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत को साइबर सिक्योरिटी में टियर 1 स्टेटस मिल गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। एक लाख 75 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। कैंसर मरीजों की दवाओं को कस्टम से मुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए काम किया है। वहाँ दिलों की दूरी को समाप्त किया है। शांति के कई समझौते हुए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। पूर्वी राज्यों के विकास की योजना पर काम शुरूकर दिया गया है। अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जम्मू-कश्मीर में 370 हटने के बाद विकास का एक नया वातावरण बना है। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ि यां निश्चित ही 2047 में विकसित और समृद्ध भारत देखेंगी।

जेजेएम प्रकरण में आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर लेने से जुड़े ईडी के मामले में आरोपी महेश मित्तल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया।

जमानत याचिका में अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट से पदम चंद जैन, पीयूष जैन और संजय बड़ाया को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, यदि संजय बड़ाया के जरिए

- याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील पेश की, मामले में चार अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को रुपए देना बताया जा रहा है तो फिर महेश जोशी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पदम चंद जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बिंदु पर सवाल खड़ा किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि उसे जेल में रखने से उसके संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 21 के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो टिप्पणियों के नाम रहा, संसद के बजट सत्र का पहला दिन

मोदी ने विदेशी चिंगारी का जिक्र किया, सोनिया के "पुअर थिंग" पर भाजपा आक्रामक हुई

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- प्रधानमंत्री ने कहा, "शायद 2014 से अब तक, यह पहला पार्लियामैंट का सत्र है, जिसके एक-दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है।"
- सोनिया गांधी ने कहा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने लंबे भाषण के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत थक गई थीं। सोनिया ने राष्ट्रपति के लिये "पुअर थिंग" शब्दों का उपयोग किया।
- भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सोनिया की टिप्पणी को "गरीब-विरोधी तथा "आदिवासी-विरोधी" बताया। केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसे राष्ट्रपति का अपमान कहा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान बताया।

नई दिल्ली, 31 जनवरी। दो, फ्रेज़ (वाक्यांश) जिनमें से एक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी में कहा और दूसरा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अंग्रेजी में), संसद बजट सत्र के पहले दिन की उल्लेखनीय बात रहीं। ये दोनों कथन आगामी जबरदस्त राजनैतिक लड़ाई के संकेत दे रहे हैं।

आज सुबह मोदी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक लोग कोई न कोई शरारत करने के लिए तैयार रहते थे तथा ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रहती थी, जो ऐसी कोशिशों में आग में घी डाला करते थे।

मोदी ने अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों की नकारात्मक सोच को प्रोजैक्ट करते हुये, विपक्ष पर अप्रत्यक्ष हमला किया और कहा, "शायद 2014 से लेकर अब तक, यह पहला पार्लियामैंट सत्र है, जिसके एक-दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है।"

जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से प्रधानमंत्री के शब्दों पर उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो कांग्रेस महासचिव ने कहा, "वे (मोदी) जनता के मुद्दों के बारे में कभी नहीं बोलते, उन्हें कभी संबोधित नहीं करते। हमने पिछले सत्र में देखा, उन्होंने बहस नहीं होने दी। इसलिये, वे तो ऐसी बातें ही कहेंगे।"

सोनिया गांधी ने एक सहज टिप्पणी की, कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को किये गये लम्बे संबोधन के "अंत तक बहुत थक गईं थीं।" राष्ट्रपति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुये, सोनिया ने उन्हें "बेचारी" (पुअर थिंग) कहा। सोनिया गांधी के इन शब्दों को लेकर एक नया राजनैतिक विवाद शुरु हो गया और भाजपा की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं होने लगीं।

यद्यपि अंग्रेजी के इन शब्दों का प्रयोग प्राय: सहानुभूति व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन भाजपा इस पर लाल-पीली हो रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रीबजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 25-26 में विकास दर कम रहेगी

पर, कैपिटल खर्च में गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत वृद्धि तथा बढ़ता हुआ डॉमैस्टिक कंज़प्शन आशा जगाता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- सर्वे में एआई के आईटी सेवाओं के निर्यात पर संभावित प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया है, जबकि इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत को इस नये वातावरण के अनुसार, परिवर्तन लाने पर विचार करना होगा।
- सर्वे ने इंगित किया है कि पूर्व में हुए सभी तकनीकी विकासों की तरह एआई की नई टैक्नोलॉजी में भी शार्ट टर्म में रोजगार कम होगा। पर, विविध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हासिल करने से रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे।

नई दिल्ली, 31 जनवरी। आज जारी किया प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे ग्लोबल जिओ पॉलिटिक्स (वैश्विक भू-राजनीतिक) और टैक्नॉलजी में प्रगति, जिसमें ए.आई. के नवीनतम विकास शामिल हैं, के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीति प्रस्तुत करता है। जिओ-इकोनॉमिक फ्रैगमैंटेशन (भू-आर्थिक विखंडन), वैश्वीकरण की जगह ले रहा है। इसका अर्थ है वैश्विक आर्थिक संरचना का टुकड़ों में बंट जाना, जिसके तहत देशों और आर्थिक ब्लॉक्स के बीच आर्थिक रिश्ते और सहयोग पहले की तुलना में कम होते जा रहे हैं, जिससे नए आर्थिक संरचना या ढांचे बन रहे हैं।

इकोनॉमिक सर्वे भविष्य की ओर देखता है और मानता है कि ऐसे में,जबकि वर्तमान भू-राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक ब्लॉकों में विभाजित है, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस उथल-पुथल के दौर से गुजरना होगा।

एक प्रकार से, सर्वेक्षण यह नोट करता है कि वैश्वीकरण का युग अब समाप्त हो चुका है और विभिन्न देश अपने आंतरिक बाज़ारों और उद्योगों की रक्षा के लिए अलग नीतियाँ बना रहे हैं तथा उपाय कर रहे हैं। भारत को संरक्षणवाद के इस नए युग में आगे बढ़ना होगा। भले ही व्यापार बढ़ रहा हो,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमने वास्तुविदों से सलाह ली है, इसलिए सदन में 200 सदस्य हैं'

जयपुर, 31 जनवरी। सालहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र में 200 सदस्य मौजूद हैं। विधानसभा में 200 विधायक कभी भी एक साथ नहीं होने के संयोग को तोड़ने के लिए वास्तु का सहारा लेने का जिक्र विधानसभा में आया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ

- विधानसभा के तीसरे सत्र में पूरे 200 विधायकों के एक साथ मौजूद होने के संयोग पर विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की

सुझाव दो-तीन वास्तु वालों के मिले हैं, दो-तीन सुझाव लागू किए हैं, एक दो और बताए गए हैं। मैं सोचता हूं, 4 साल पूरे 200 के 200 सदस्य बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

गौरतलब है कि वास्तुविदों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राष्ट्रपति का अपमान तो भाजपा ने संसद भवन उद्घाटन व राम मंदिर में नहीं बुलाकर किया'

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे व प्रियंका ने कहा कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं

- प्रियंका ने कहा, "मेरी मां ने सिर्फ इतना भर कहा कि राष्ट्रपति ने इतना लम्बा भाषण पढ़ा और वह थक गई होंगी, बेचारी। उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।"

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि गांधी और कांग्रेस किसी का अपमान नहीं करती है।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ही राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान भाजपा ने नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह में तथा राम मंदिर में रामलला को विराजमान करते समय ही कर दिया था, दोनों कार्यक्रमों में मुर्मु को आमंत्रित नहीं किया गया।

खड़गे ने कहा महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नयी संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। कांग्रेस या हमारे नेता कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर - दोनों से हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति जी को भाजपा ने ही जान बूझकर दूर रखा था।

प्रियंका ने कहा, मेरी मां 78 साल की हैं और उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा और वह थक गई होंगी, बेचारी। मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं और उनकी टिप्पणी को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

गौरतलब है कि गांधी की टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के, संसद के संयुक्त सदन में अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आदिवासी समुदाय का अपमान करार दिया है।

राज्यपाल ने डोटासरा को डांट लगाई

जयपुर, 31 जनवरी (वि.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को विधानसभा में अभिभाषण के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को डांट लगा दी। दरअसल डोटासरा अभिभाषण के बीच में बार-बार खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे थे, इस पर राज्यपाल ने भी तल्ख लहजे में जवाब दिया।

डोटासरा ने राज्यपाल की जिलेवार बैठकें करने पर तंज कसते हुए कहा कि, "सरकार तो बैठक कर नहीं रही है और आप जिलों में जाकर

- डोटासरा, अभिभाषण के दौरान बार-बार खड़े होकर टोकाटोकी कर रहे थे।

बैठक कर रहे हो।"

इस पर राज्यपाल बागड़े ने तीखे अंदाज में डोटासरा को जवाब देते हुए कहा, "जनजाति हितों से जुड़ी समिति मेरे विभाग में आती है और उसकी बैठक करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। मैं हर जिले में जाऊंगा और वहां बैठक करूंगा।"

विधानसभा में हाल के वर्षों में यह पहला मौका है, जब टोका-टाकी होने पर राज्यपाल ने किसी विधायक को व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया हो।

इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा सदन में अभिभाषण पूरा पढ़कर सुनाया जाना भी लंबे समय बाद हुआ है। पिछले कई साल से अलग-अलग कारणों से राज्यपाल के अभिभाषण पूरे नहीं पढ़े गए।

कई बार विपक्ष के हंगामे की वजह से भी अभिभाषण पूरे नहीं पढ़े गए तो कई बार राज्यपाल की तबीयत की वजह से भी अभिभाषण पढ़े हुए माने जाते रहे।

कांग्रेस सरकार के "जल जीवन मिशन" घोटाले से राजस्थान की साख खराब हुई

राज्यपाल बागड़े ने अभिभाषण में कहा कि भजनलाल सरकार में एक भी परीक्षा का पेपरलीक नहीं हुआ

-विधानसभा संवाददाता-

- "पिछली कांग्रेस सरकार में राजनीतिक लाभ के लिये पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट अटकाया जाता रहा। वर्तमान सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिये 12 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरु कर दिया।"
- "गहलोत सरकार के वक्त प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ने परसा ईस्ट ब्लॉक से कोयले का खनन फिर से शुरु किया। अब हमारे थर्मल पावर प्लांट को भरभूर कोयला मिल रहा है।"

जयपुर, 31 जनवरी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा में कहा कि "पिछली कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के कारण राजस्थान की साख देश भर में खराब हुई। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय कई भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक हुए और परीक्षाओं में देरी हुई। परंतु भजनलाल सरकार ने पिछले 1 साल में पेपरलीक मामलों में 100 से ज्यादा एफ.आई.आर. दर्ज करके, 260 लोगों को गिरफ्तार किया है। साल 2025 के दौरान 81 हजार पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों का प्रतीक है। हमारी सरकार में एक भी परीक्षा का पेपरलीक नहीं हुआ।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के प्रथम दिन करीब 1 घंटे 26 मिनट अभिभाषण पढ़ा। इस दौरान, उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को पेपरलीक, जल जीवन मिशन घोटाले, थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी, राजस्थान में बिजली संकट समेत कई मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही, भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल में "राम जल सेतु लिंक परियोजना," यमुना जल योजना व जल संरक्षण के लिए किये गए कार्यों को सराहा।

राज्यपाल ने कहा कि, पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को सबसे पहले वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू किया था। दुर्भाग्य से, विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता रहा। हमारी सरकार ने इसे राम जल सेतु परियोजना का नाम दिया। मध्य प्रदेश के साथ इस परियोजना को लेकर एमओयू

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के प्रथम दिन करीब 1 घंटे 26 मिनट अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को पेपरलीक, जल जीवन मिशन घोटाले, थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी, राजस्थान में बिजली संकट सहित कई मुद्दों पर घेरा।